>

Title: Need to provide reservation of jobs to muslims in Central Government Services.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अल्पसंख्यक वर्ग में विशेÂष रूप से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति एवं शैक्षणिक रोजगार की स्थिति पर मंडल कमीशन की तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद यह मांग जोर-शोर से उठाई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय में खासतौर से उस वर्ग के लोगों की, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, उन्हें अलग से आरक्षण दिया जाए । मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर हिन्दू पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या की संख्या 8.44 प्रतिशत दिखाई गई है, उसी को आधार मानकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई । प्रावधान होने के बावजूद बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है । केन्द्रीय न्याय मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व यह उल्लेख किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान केन्द्र सरकार की नौकरियों में जल्द ही होने जा रहा है इससे इस समाज के लोगों में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई है ।

मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के स्तर से केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण का शीघ्र प्रावधान किया जाए और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दे दिए जाएं कि वे अपने स्तर से भी ऐसी व्यवस्था को लागू करें ।